कार्यकारी आदेश 2025-05

एच.आर. 1 के अभूतपूर्व आर्थिक और राजकोषीय प्रभाव के लिए इलिनॉय राज्य को तैयार करने से संबंधित कार्यकारी आदेश

चूंकि, 4 जुलाई, 2025 को संघीय सरकार ने सार्वजनिक कानून 119-21 (कांग्रेस के 119वें अधिवेशन का सदन संकल्प 1) (एच.आर. 1) अधिनियमित किया, जिसके तहत राज्य सरकार की वित्तीय दिशा पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कई परिवर्तन किए गए हैं; और,

चूंकि, अन्य नई संघीय आर्थिक नीतियों सहित एच. आर. 1 के प्रभाव - जिसमें कामकाजी परिवारों पर कर के समान व्यापक कर शामिल हैं - अमेरिका की आर्थिक गिरावट को तेज करेंगे, धन की असमानता को बढ़ाएंगे, और इलिनॉय के व्यवसायों को नुकसान पहुंचाएंगे; और,

चूंकि, इलिनॉय मध्य-पश्चिम का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है, जहां 2023 में $13.7 बिलियन का कृषि निर्यात किया गया था। इलिनॉय के किसान निर्यात पर निर्भर हैं और इसके नतीजतन, राज्य के कृषि उद्योग को करों के कारण अभूतपूर्व बाधाओं का सामना करना पड़ा है; और,

चूंकि, संघीय नीतियां इलिनॉय की सकारात्मक आर्थिक प्रगति के लिए खतरा बन रही हैं। इलिनॉय ने 2022 में पहली बार $1 ट्रिलियन का सकल घरेलू उत्पाद हासिल किया, और तब से सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हो रही है; और,

चूंकि, अर्थशास्त्री संभावित आर्थिक मंदी की चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (बीएलएस) द्वारा अगस्त 2025 में पेश की गई नौकरियों से जुड़ी रिपोर्ट से पता चला है कि देश भर में नियोक्ताओं ने केवल 22,000 नौकरियों का सृजन किया और राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 2021 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई; और,

चूंकि, एच. आर. 1 इतिहास के सबसे बड़े धन हस्तांतरणों में से एक है, जिससे अरबपतियों को करों में स्थाई छूट मिलती है और कर छूट को बढ़ावा देने के लिए औसत और मध्यम आय वाले अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सहायता सहित महत्वपूर्ण सहायता को हटा देता है; और,

चूंकि, बजट प्रबंधन के दौरान, राज्य को हाल ही में संघीय नीति में किए गए परिवर्तनों के नकारात्मक प्रभावों के साथ-साथ दीर्घकालिक संघीय सहायता कार्यक्रमों में एच. आर. 1 की कटौती से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना होगा, जिसमें पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (एसएनएपी) की लागत का अभूतपूर्व बोझ राज्य पर डाला गया है, और संघीय मेडिकेड फंडिंग में बड़े पैमाने पर प्रत्याशित कटौती की गई है; और,

चूंकि, एच. आर. 1 मेडिकेड में व्यापक बदलावों को भी अनिवार्य बनाता है और सुलभ स्वास्थय देखभाल अधिनियम (एसीए) कवरेज को अधिक महंगा और कम सुलभ बनाता है, जिससे बिना बीमा वाले अमेरिकियों की संख्या में काफी वृद्धि होगी और स्वास्थ्य सेवा उद्योग में लागत बढ़ जाएगी; और,

चूंकि, एच. आर. 1 के कारण स्वास्थ्य देखभाल में होने वाले महत्वपूर्ण और नकारात्मक परिवर्तनों के नतीजतन राज्य को राजस्व की हानि हो सकती है, और इसके साथ ही चिकित्सा कवरेज और नौकरियों में नुकसान भी होगा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में; और,

चूंकि, इलिनॉय में ग्रामीण और सुरक्षा नेट अस्पताल संवेदनशील आबादी के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करते हैं, और एच. आर. 1 के कारण मुआवजा रहित देखभाल में अनुमानित वृद्धि और संघीय मेडिकेड फंडिंग में होने वाली कमी उनकी आर्थिक स्थिरता को खतरे में डालती है, जिससे अस्पताल बंद होने का खतरा होता है और ग्रामीण और पिछड़े शहरी समुदायों में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच कम हो जाती है; और,

चूंकि, एच. आर. 1 में कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए कर कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं, जिनका वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) के दौरान राज्य के राजस्व पर और निकट भविष्य के लिए राज्य के राजस्व दृष्टिकोण पर तत्काल प्रभाव पड़ने की उम्मीद है; और,

चूंकि, बड़े निगमों और धनी अमेरिकियों के लिए एच. आर. 1 में शामिल कर छूट, वित्तीय वर्ष26 और उसके बाद इलिनॉय के अनुमानित राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि इलिनॉय, कई अन्य राज्यों की तरह, अपने कर कोड के प्रमुख हिस्सों को संघीय कर कोड से जोड़ता है, जिसका अर्थ यह है कि संघीय कानून में किए गए परिवर्तन अपने आप राज्य के राजस्व को प्रभावित करते हैं।; और,

चूंकि, संतुलित बजट बनाए रखने और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य को अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने और भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए रिज़र्व फंड तैयार करने हेतु तुरंत और निर्णायक कार्यवाही करनी होगी।

अब, इसलिए, मैं, जे. बी. प्रिट्ज़कर, इलिनॉय का राज्यपाल, इलिनॉय संविधान और इलिनॉय राज्य के कानूनों द्वारा मुझे प्राप्त कार्यकारी अधिकार के आधार पर निम्नलिखित आदेश देता हूं:

I. वित्तीय वर्ष 2026 बजट प्रबंधन और आरक्षित निधि

इस कार्यकारी आदेश से जुड़े उद्देश्यों के लिए, शब्द "राज्य एजेंसी" या "राज्य एजेंसियां" का अर्थ होगा - राज्य सरकार की कार्यकारी शाखा का कोई भी कार्यालय, विभाग, बोर्ड, आयोग या संस्थान। यह आम सभा, राज्य सरकार की न्यायिक शाखा, महान्यायवादी, राज्य सचिव, राज्य लेखा परीक्षक, राज्य कोषाध्यक्ष या ऐसे अधिकारियों द्वारा प्रशासित किसी भी इकाई, कार्यकारी महानिरीक्षकों के कार्यालयों, किसी भी सार्वजनिक कॉलेज या विश्वविद्यालय या किसी भी राज्य सेवानिवृत्ति प्रणाली पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा, यह शब्द कार्यकारी नैतिकता आयोग, राज्य चुनाव बोर्ड इलिनॉय पावर एजेंसी, या राज्य शिक्षा बोर्ड पर लागू नहीं होता है।

इस आदेश के 30 दिनों के अंदर, राज्य एजेंसियों को राज्यपाल के कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें बजट और आरक्षित निधि प्रबंधन की निम्नलिखित रणनीतियों पर प्रगति की रूपरेखा शामिल होगी:

a. **राज्य एजेंसी बजट समीक्षा।** राज्यपाल कार्यालय और राज्यपाल के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय (जीओएमबी) के साथ मिलकर, प्रत्येक राज्य एजेंसी अपने बजट और व्यय योजना की समीक्षा करेगी, ताकि व्यय में संभावित तत्काल कटौती की पहचान की जा सके, जिसमें ऐसी दक्षताएं भी शामिल होंगी, जिनके नतीजतन व्यय में कमी आएगी।
b. **राज्य एजेंसी रिजर्व।** जितना हो सके, और आवश्यक कार्यों को रोके बिना, प्रत्येक राज्य एजेंसी को राज्य कोष और अन्य संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे, जिसमें FY26 सामान्य कोष आवंटनों का 4 प्रतिशत हिस्से को आरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
c. **कटौती, हस्तांतरण और कार्यक्रम से जुड़े परिवर्तन।** यदि राज्य एजेंसी के शीर्ष अधिकारियों को एजेंसी के बजट में संभावित वित्तीय वर्ष26 की कमियों का पता चलता है, तो उन्हें विधाई हस्तांतरण के जरिए कम की जाने वाली बजट लाइनों की पहचान करनी

होगी या कार्यक्रम से जुड़े संभावित परिवर्तनों की पेशकश करनी होगी, जो उन पूरक व्यय के बोझ को कम कर सकते हैं।

d. **एजेंसी बजट प्रबंधन।** जीओएमबी के साथ मिलकर, प्रत्येक राज्य एजेंसी अनावश्यक खरीद और परिचालन व्यय पर रोक लगाएगी; एजेंसी के संचालन के लिए अनावश्यक यात्रा को समाप्त करेगी; और सभी संभावित नियुक्तियों की समीक्षा करेगी और उन्हें प्राथमिकता देगी।

II. बचत प्रावधान

यह कार्यकारी आदेश न तो किसी संघीय या राज्य कानून या विनियमन नियम का उल्लंघन करता है और न ही इसे किसी नियम का उल्लंघन करने वाला समझा जाएगा। यह कार्यकारी आदेश किसी भी तरह से वर्तमान में प्रभावी अनुबंधों, समझौतों या सामूहिक सौदेबाजी समझौतों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगा।

III. पृथक करने की क्षमता

यदि इस कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति में सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अमान्य ठहराया जाता है, तो यह अमान्यता किसी अन्य प्रावधान या इस कार्यकारी आदेश के अमल को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अमान्य प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक करने योग्य घोषित किया जाता है।

IV. प्रभावी तिथि

यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट) के पास इसे दायर किए जाने पर तत्काल प्रभावी हो जाएगा।

_____

जे. बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी: 23 सितंबर, 2025
राज्य सचिव के समक्ष दायर किया गया: 23 सितंबर, 2025